# खिलाड़ियों की पीठ पर सवार होने का प्रयास करती खट्टर सरकार

**फ़रीदाबाद (म.मो.)** बीते सप्ताह मुख्यमंत्री खट्टर ने अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए तमाम बड़े अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया। लाखों रुपये खर्च करके छपवाये विज्ञापन में खट्टर जी बताते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले कुल 79 भारतीय खिलाड़ियों में से 30 हरियाणा के हैं और बीच में अपना खुद का बड़ा सा फ़ोटो इस अंदाज में लगवा रखा है मानो कह रहे हों कि ये तमाम खिलाड़ी, ओलंपिक में जाने लायक उन्होंने ही बनाये हैं।

वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह इसके विपरीत है। सरकार की ओर से इन्हें परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये खिलाड़ी आज जो कुछ भी बन पाये हैं अपने दम-खम, अपने खर्चे व मेहनत से बन पाये हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का नमूना देखना हो तो यहां का सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर उपलब्ध है। इस में एस्कॉर्ट कम्पनी द्वारा बनवा कर दिया गया तरणताल (स्विमिंग पूल) सरकार ने ठेकेदार को बेच दिया क्योंकि सरकार के पास उसकी देख-भाल एवं सम्भाल करने का पैसा नहीं है। इसी तरह लॉन टेनिस, बेड मिंटन बास्केट-बॉल कोर्ट भी ठेकेदार को बेच दिये हैं। ठेकेदार यहां खेलने वालों से बाकायदा मासिक शुल्क लेकर लाखों कमाता है। इसी तरह जिम भी ठेकेदार के हवाले कर रखा है।

हॉकी, फुटबॉल, वाली बॉल, बास्केट बॉल, कुश्ती, बॉक्सिन की कोई व्यवस्था नहीं है। न प्रशिक्षक हैं न ढंग के पर्याप्त मैदान। खेल परिसर के गेट ऐसे बंद रखे जाते हैं जैसे जेल के हों, खिलाड़ी इधर-उधर से कूद-फ़ांदकर या ग्रिलें तोड़ कर भीतर आते हैं। खेल मैदानों के अभाव में बच्चे इधर-उधर भटकते हैं। इसका लाभ नहर पार के कुछ खेत मालिक तो उठा ही रहे हैं जो खिलाड़ियों से नकद वसूली करते हैं बल्कि कुछ माफ़िया तो सरकारी जगहों व पार्कों आदि पर कब्जे जमाकर खिलाड़ियों से मोटी वसूली कर रहे हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं सेक्टर 12 स्थित टाऊन पार्क में ही 8

लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं। ये लोग बाकायदा अस्थाई बाऊंडरी बना कर अपने पेमेंट करने वाले सदस्यों को खिलाते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम राहुल का है जिसके पास करीब 60-70 सदस्य हैं जो मासिक 3000 की पेमेंट करते हैं। इन्होंने यहां बेटलिफ्टिंग का सामान, डंम्बल, टायर, रस्से आदि सामान लाकर रखे हुए हैं रोजाना लगभग तीन-चार गाड़ियों में इनका सामान आता और जाता है। इनके क्षेत्र में जरा भी घुसने वाले से ये लोग मार-पीट पर उतारू हो जाते हैं। इस बाबत थाना सेंट्रल में एफ़आईआर तक भी दर्ज हो चुकी है, सीएम विंडों पर भी शिकायत लग चुकी है, और तो और विधायक बनने से पूर्व नरेन्द्र गुप्ता के साथ भी इसने बदतमीज़ी की थी, लेकिन विधायक बनने के बाद जब लोगों ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो वे बोले क्या करें लोगों के सिफ़ारिशी फ़ोन आ जाते हैं।

जो सरकार अपने बच्चों को खेलने के लिये मैदान तक भी उपलब्ध न करा सके उसे क्या हक है खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सेहरा अपने सिर पर बांधने का? गौरतलब है कि उक्त तमाम 30 खिलाड़ी कुश्ती, बाक्सिंग, एथलेटिक्स शूटिंग आदि की ऐसी खेलों से हैं जिसे वे अपने खूद के दम पर यानी बिना किसी सरकारी सहयोग के कर सकते हैं। सभी खिलाड़ी खेल, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अकरमण्यता से त्रस्त हैं। ऐसे में उन्होंने सरकारी खेल विभाग के भरोसे रहने की अपेक्षा अपने दम पर संघर्ष में उतरना पड़ा।

### सरकार केवल झूठे वायदे कर सकती है

जुमलेबाज़ों की यह सरकार केवल जुमलों से ही खिलाड़ियों को बहलाये रखने में विश्वास करती है। मोटे-मोटे इनामों व नौकरियों की घोषणा तो कर देती है परन्तु देने के वक्त नौटंकी करने लगती है। उन पदक विजेताओं की लिस्ट काफ़ी लम्बी है जिन्हें सरकार ने वायदेनुसार न तो नौकरी ही दी और न ही धन राशि। अब फ़िर घोषणा कर डाली कि ओलांपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ देंगे, जीतने के बाद सरकार नहीं देगी तो इसका कोई क्या कर लेगा? सरकार के दुर्भाग्य से यदि सभी 30 खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले आये तो 180 करोड़ कहां से देंगे खट्टर जी, वेतन तक के लाले पड़े हैं।

### खिलाड़ियों का राजनीतिक दुरूपयोग

खेल जगत में नाम रोशन कर के सेलिब्रेटी बने लोगों को भाजपा अपना गमछा ओढा कर चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है। हॉकी प्लेयर संदीप सिंह पर तो भाजपा का दांव सफ़ल रहा लेकिन पहलवान बबीता फ़ोगाट व रामेश्वर दत्त पर फ़ेल हो गया। रामेश्वर दत्त पर तो बल्कि दो बार दांव खेला गया और दोनों बार दत्त खोटा सिक्का साबित हुआ। दरअसल इस मामले में मतदाता ने अपनी सूझ-बूझ का परिचय देते हुए अपनी राजनीतिक जागरूकता दिखाई है। उनका मानना है कि खिलाड़ी खेलता अच्छा है तो जरूरी नहीं कि रातजनीति भी अच्छी ही करेगा; हालांकि देश में इस तरह की जागरूकता का नितांत अभाव होने के चलते अनेको नाचने-गाने वाले भांड भी सांसद बने बैठे हैं जो जनता के किसी काम के नहीं।

# फर्जी एस्टीमेट का दोषी.....

पेज एक का शेष

### कार्यकारी अभियंता विवेक गिल को प्रमोशन

कमिश्नर गरिमा मित्तल ने कार्यकारी अभियंता विवेक गिल और एसडीओ के विरुद्ध कार्रवाई के लिये सचिव एस.एन. रॉय को लिखा; लेकिन चंद दिनों बाद ही एमसीएफ कमिश्नर को एक पत्र मिलता है, जिसमें सूचित किया जाता है कि कार्यकारी अभियंता विवेक गिल को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एसई) पद पर प्रमोट करते हुए उन्हें गुड़गांव नगर निगम में तैनात किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि इस पत्र के आने के बाद गरिमा मित्तल ने एस.एन. रॉय से बात की और विरोध जताया कि जिस इंजीनियर के खिलाफ जांच रिपोर्ट है और उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा, उसे प्रमोशन कैसे दी जा सकती है? बताया जाता है कि एस.एन. रॉय ने निगम कमिश्नर से कहा कि किसी जांच रिपोर्ट में कुछ भी लिख दिए जाने से उस अफसर की प्रमोशन प्रभावित नहीं होती है। इसलिए विवेक गिल को प्रमोशन दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक यह मामला चीफ सेक्रेटरी के दरबार में भी पहुंचा लेकिन वहां से भी निगम कमिश्नर को सहारा नहीं मिला। इसका नतीजा यह निकला कि निगम कमिश्नर नाराज होकर अब एमसीएफ के दफ्तर में ही नहीं आतीं। वो सारी फाइलें स्मार्ट सिटी दफ्तर में ही मंगा लेती हैं। मीटिंग वगैरह भी वहीं करती हैं। जाहिर है भ्रष्टाचारियों की शिकायत ऊपर भेजकर उन्होंने अपनी फ़जीहत ही कराई। इसके विपरीत यदि वो चाहती तो बड़े आराम से उक्त लूट में अपना हिस्सा लेकर डकार सकती थी। उनकी यह ईमानदारी किस काम आई? इस मामले से जहां एक ओर कमिश्नर हतोत्साहित हुई हैं वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों के हौंसले बुलंद होना स्वाभाविक हैं।

### प्रमोशन के लिए नियम तोड़े गए

एक्सईएन से एसई बनाए गए विवेक गिल के लिए शहरी निकाय विभाग ने अपने ही नियमों को तोड़ दिया। विवेक गिल 2009 में नगर निगम में भर्ती हुआ था। उसे 2017 में एक्सईएन बनाया गया। लेकिन एसई बनाते समय यह नियम है कि एक्सईएन के पास कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन यहां तो विवेक गिल के पास पांच साल का ही अनुभव था, फिर उसे एसई कैसे बना दिया गया। शहरी निकाय विभाग ने अपना ही नियम तोड़ते हुए उसे तीन साल की छूट देते हुए उसे 2017 में एक्सईएन पोस्ट पर मिली प्रमोशन को 2014 से दिखा दिया गया। यानी हरियाणा शहरी निकाय विभाग ने उसे 2014 से एक्सईएन बनाना अपने रेकॉर्ड में दिखा दिया। इस तरह आठ साल का फर्जी क्राइटेरिया पूरा किया गया। अगर यह मान भी लिया जाए कि उसे तीन साल पीछे से नियमों में ढील देकर प्रमोशन दी गई तो शख्स 2009 में भर्ती हुआ तो उस गैप को कौन पूरा करेगा। उस गैप को पूरा करने के लिए विवेक गिल की नगर निगम में भर्ती 2006 से दिखानी पड़ेगी। कोई ताज्जुब नहीं कि शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन. रॉय यह कारनामा भी अंजाम दे दें।

### पैसे दो, एस.एन. रॉय के दफ्तर में कुछ भी करा लो

नगर निगम फरीदाबाद और गुड़गांव में तबादला, प्रमोशन, शिकायत दबाने, जांच दबाने, कारण बताओ नोटिस जारी कराने के लिए हरियाणा शहरी निकाय विभाग चंडीगढ़ में बाकायदा रेट तय हैं। चंडीगढ़ में बैठे अफसरों के एजेंट फरीदाबाद और गुड़गांव में बैठे हुए हैं। एस.एन. रॉय के दफ्तर का बाबू 50 हजार रुपये की रिश्वत लेकर इन मामलों से संबंधित नोटिंग बनाता है। फिर उसे पेश करने और आगे काम कराने के लिए मोटी रिश्वत वसूली जाती है। यह रेट पद के हिसाब से है। जेई को यही काम कराने के लिए पहले 50 हजार और फिर पांच लाख देने पड़ते हैं। एक्सईएन, एसई आदि से दस लाख रुपये से नीचे बात ही नहीं बनती। फरीदाबाद और गुड़गांव में बैठे एजेंट बीच में 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये अपनी फीस भी रखते हैं।

एस. एन. रॉय के दफ्तर के कुछ चपरासी तक साहब से मिलाने का पैसा लेते हैं। उनके दफ्तर में पूरी चेन है। इसमें एस. एन, रॉय शामिल हैं या नहीं, यह साफ नहीं है। लेकिन उनका दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इस आरोप से वो बच नहीं सकते।

# सीमा त्रिखा ने लुटाया खजाना

पेज एक का शेष

क्लब ने तय किया कि संस्था के हर सदस्य को एक-एक लैपटॉप दिया जाए। एक लैपटॉप की कीमत 40 हजार रुपये बताई गई। सिटी प्रेस क्लब के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमने ईमानदारी से करीब 50-55 सदस्यों को एक-एक लैपटॉप बांट दिए। कुछ अन्य सदस्यों ने भी लैपटॉप मिलने की पुष्टि की। दरअसल, चुनाव में इन पत्रकारों की पत्रकारिता से प्रभावित होकर सीमा त्रिखा ने सीपीएस बनने के बाद हरियाणा सरकार के खजाने से 21 लाख रुपये 7 दिसम्बर 2015 को दिलाए थे। पाठकों को याद होगा कि 2014 में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में पत्रकारों ने बहुत मेहनत की थी। भाजपा ने खासतौर पर सहयोग के लिए फरीदाबाद के पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया था। हालांकि भाजपा ने ऐसी प्रशंसा देशभर में हर शहर में पत्रकारों की थी।

**पांचाल सभा जवाहर कॉलोनी** को भी सीमा ने जनवरी 2018 में 21 लाख रुपये की ग्रांट दी। सीमा ने जवाहर कॉलोनी में तमाम धार्मिक संस्थाओं को चुन-चुन कर सरकारी पैसे बांटे। आगे आपको उनका विवरण मिलेगा।

**क्षत्रीय सभा बल्लभगढ़** को 21 लाख रुपये भवन बनाने के लिए जनवरी 2018 में सीमा त्रिखा ने सरकारी खजाने से दिए।

### और भी कृतार्थ हुए

**फरीदाबाद धार्मिक और सामाजिक संगठन** को पांच लाख रुपये की ग्रांट सीमा त्रिखा ने 12 जुलाई 2017 को दिलाई। उसे यह पैसा मालवीय वाटिका दशहरा ग्राउंड में धार्मिक गतिविधियों के लिए मिला था। मालवीय वाटिका को एमसीएफ ने उजाड़ दिया है, क्योंकि इसे सरकारी जमीन पर अवैध करके जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। इस संस्था को जोगिन्दर चावला वगैरह चलाते हैं और संस्था को लेकर तमाम विवाद है। धार्मिक सामाजिक संगठन को 20 लाख रुपये की दूसरी ग्रांट 2018 में सीमा ने दी। इस तरह सीमा ने अकेले इस संगठन पर लगातार दो साल कृपा बरसाई।

**शक्ति सेवा दल** को 9,45,050 रुपये धर्मार्थ अस्पताल के लिए दिए गए। लेकिन शक्ति सेवा दल चिमनीबाई धर्मशाला का संचालन करता है। चिमनीबाई धर्मशाला में कम से कम फिलहाल कोई धर्मार्थ अस्पताल खुले की सूचना नहीं है। अगर यह अस्पताल चिमनीबाई धर्मशाला में अंडरग्राउंड चल रहा हो तो अलग बात है। शक्तिसेवा दल को ये पैसे 7 दिसम्बर 2015 को सरकारी खजाने से दिए गए थे।

**श्रीराम जी धर्मार्थ अस्पताल सोसाइटी** को सीमा त्रिखा ने 20 मार्च

कंवल खत्री

2018 को चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए 11 लाख रुपये हरियाणा सरकार से दिलवाए। लेकिन श्रीराम अस्पताल में इस पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा गया। अस्पताल को चलाने वाली संस्था के बीच आपसी विवाद है, जिसमें सीमा त्रिखा समर्थक गुट ने एनआईटी में कई स्थानों पर कहा कि यह सरकारी ग्रांट जो आती है, इसमें से हमें कुछ पैसा वापस करना पड़ता है। पाठक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बात का क्या अर्थ है और वो पैसा कहां वापस जाता है।

**विजय रामलीला कमेटी** को रामलीला का स्टेज और हॉल बनाने के लिए 11,00,000 रुपये 7 दिसम्बर 2015 को सीमा त्रिखा ने हरियाणा सरकार के खजाने से दिलवाए। इसके बाद 2018 में भी विजय रामलीला कमेटी को सीमा ने धर्मशाला बनाने के लिए 11 लाख की सरकारी ग्रांट दी।

**आर्य समाज जवाहर कालोनी** को तीन लाख रुपये की सरकारी ग्रांट सीमा त्रिखा ने 12 जुलाई 2017 को दी। श्री सनातन धर्म सभा जवाहर कालोनी को भी सीमा त्रिखा ने 12 जुलाई 2017 को ढाई लाख की ग्रांट दी। **अखिल भारतवर्षीय सनातम धर्म महावीर दल** फरीदाबाद को 11 लाख रुपये सीमा ने 2018 में दिए। इस तरह सीमा ने न सिर्फ आर्य समाज को बल्कि सनातन धर्म को भी साधा।

बडखल गांव की **श्री गोपाल गौशाला** को पूर्व सीपीएस ने गायों का शेड बनाने के लिए पांच लाख रुपये 7 दिसम्बर 2015 में दिलाए। इसी तरह श्रीकृष्ण चौदसी गौशाला होडल को 2018 में सीमा ने 11 लाख रुपये की ग्रांट दी।

**जिला टैक्स बार एसोसिएशन** को फर्नीचर और किताबें खरीदने के लिए पांच लाख रुपये सरकारी खजाने से दिए गए। हर शहर में टैक्स बार एसोसिएशन सबसे धनी होती है, लेकिन फरीदाबाद की एसोसिएशन को सरकारी आर्थिक मदद की जरूरत क्यों पड़ी, यह कोई नहीं जानता। एसोसिएशन के लोगों से सीमा त्रिखा के पति के अच्छे संबंध हैं।

किसी **गौतम फाउंडेशन** को पांच लाख रुपये गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कराने के लिए पूर्व सीपीएस ने सरकारी खजाने से दिया। यह अच्छा काम है। हमने गौतम फाउंडेशन के पते पर बहुत तलाश की ताकि उन लोगों का परिचय लेकर एक बड़ी खबर छापी जा सके, लेकिन गौतम फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मजदूर मोर्चा के पाठकों को इसकी जानकारी हो तो सूचित करें। इस एनजीओ की और भी मदद होनी चाहिए लेकिन इनका पता-ठिकाना तो मिले। सीमा त्रिखा ने गौतम फाउंडेशन के लिए फंड 20 जनवरी 2018 को जारी कराया था।

**प्रभाती जत्था एनएच 2ई ब्लॉक** को तीन लाख रुपये जुलाई 2017 में सीमा त्रिखा ने दिलाए। यह पैसा इस संस्था को ब्लड डोनेशन कैंप लगाने और ट्रस्ट की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिए गए। एनएच 2 ई ब्लॉक के निवासियों का कहना है कि प्रभाती जत्थे ने कभी कोई रक्तदान शिविर नहीं लगाया। किसी और इलाके में जाकर लगाया हो तो अलग बात है।

**श्री महाराजा अग्रसेन फाउंडेशन** अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 37 फरीदाबाद को खेल गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 12 जुलाई 2017 में तीन लाख रुपये सरकारी खजाने से सीमा त्रिखा ने दिलाए। उम्मीद है कि अशोका एन्क्लेव में खेल गतिविधियां चरम पर पहुंच गई होंगी।

**हरियाणा किक बॉक्सिंग एसोसिएशन** सेक्टर 49, फरीदाबाद को खेल का सामान खरीदने के लिए पूर्व सीपीएस ने हरियाणा सरकार से तीन लाख की ग्रांट 2017 में दिलाई।

**जिला आर्चरी एसोसिएशन** को 2017 में ही खेल का सामान खरीदने के लिए सरकार से तीन लाख रुपये सीमा त्रिखा ने दिलाए।

सेक्टर 8 की **राजकुल सांस्कृतिक संस्था** को एसी खरीदने के लिए सीमा त्रिखा ने सरकार के तीन लाख रुपये दिलाए।

**शहीद भगत सिंह सेवा सदन** एसी नगर फरीदाबाद को ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए पांच लाख रुपये की ग्रांट सीमा त्रिखा ने 2017 में दी।

**के.एल. मेहता दयानंद महिला कॉलेज** को खेल गतिविधियों और लाइब्रेरी की किताबों के लिए सीमा त्रिखा ने जुलाई 2017 में तीन लाख की ग्रांट दी। इस कॉलेज के पास खुद बहुत पैसा है, इसके बावजूद कॉलेज की लाइब्रेरी की हालत दयनीय है। सीमा त्रिखा का दिया पैसा कहां खर्च हुआ, यह कॉलेज प्रबंधन ही बेहतर जानता होगा।

आरएसएस से जुड़े संगठन **भारत विकास परिषद** सेक्टर 7 ई को सेक्टर 8 के श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कराने के लिए 11 लाख रुपये सीमा ने सरकारी खजाने से दिए। मजदूर मोर्चा के पाठक खुद जाकर सेक्टर 8 में इस श्मशान की दशा और यहां खर्च किए गए 11 लाख रुपये की दिशा का जायजा ले लें।

### पैसा जाता है, फिर लौट आता है

जनता जो टैक्स भरती है, उसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में विभिन्न मदों में रखा जाता है। इसमें एक मद यह भी है कि मंत्री चाहे तो समाज में एकता, जागरूकता को बढ़ावा देने वाले एनजीओ, व्यक्तियों को आर्थिक मदद दे सकती है। लेकिन मंत्री और नेता इसे अपनी लोकप्रियता के लिए इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस और भाजपा में बस इतना फर्क है कि कांग्रेसी शासनकाल के मंत्री धार्मिक संगठनों, धार्मिक स्थलों, विवादास्पद एनजीओ को ऐसी ग्रांट देने से बचते थे। लेकिन भाजपा शासनकाल में सरकारी खजाने के ऐसे पैसे का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ज्यादातर सरकारी ग्रांट आरएसएस से जुड़े संगठनों, एनजीओ, धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को दी जा रही है। सीमा त्रिखा ने बतौर सीपीएस जो पैसा लुटाया है, उसकी सूची से इसकी पुष्टि होती है। सरकारी आर्थिक मदद एक रैकेट है, जिसे नेता संगठित ढंग से चला रहे हैं। आरोप है कि कई बार जो पैसा एनजीओ और संस्थाओं को मिलता है, उनसे उसका कुछ हिस्सा वापस मांग लिया जाता है। मंत्री के ही नजदीकी लोग इन तथ्यों को बता देते हैं।